



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 1991/अग्राहायण 5, 1913  
No. 430] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 1991/ AGRAHAYANA 5, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1991

सा. का. नि. 699(प्र):— केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के दुर्व्यवहार तथा अक्षमता की जांच करने की कार्यविधि को विनियमित करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:— (1) इन नियमों को रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की कार्यविधि) नियम, 1991 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में:—

- (क) "न्यायाधीश" से नियम 3 के अधीन जांच के लिए नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है।
- (ख) "सदस्य" से रेल बाधा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 3 के अधीन स्थापित रेल बाधा अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसे अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष शामिल हैं, जिसके विरुद्ध इन नियमों के अधीन दुर्व्यवहार या अन्याय की जांच की जा रही है,
- (ग) इसमें उपलब्ध किए गए और परिभाषित न किए गए बल्कि रेल बाधा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 5) में परिभाषित किए गए शब्दों और वाक्यांशों का वह अर्थ होगा, जो उन्हें उक्त अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

3. जांच करने के लिए न्यायाधीश :— (1) जब कभी भी केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी सदस्य के दुर्व्यवहार या उस पर अन्याय के आरोप की सत्यता की जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसी जांच के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना ऐसे सदस्य को भी दी जाएगी।

4. न्यायाधीश की कृतियां :— (1) न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित कार्यविधि द्वारा बाधित नहीं होगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा तथा उसे जांच किए जाने के स्थलों और समय को तय करेगा सहित अपनी कार्यविधि विनियमित करने की शक्ति भी होगी।

(2) न्यायाधीश को, इन नियमों के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे पर कार्यवाही करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

- (क) किसी व्यक्ति को सम्मन भेजना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ दिलाकर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उन्हें पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी कार्यालय से लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना।

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1991

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the procedure for investigation of misbehaviour and incapacity of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Railway Claims Tribunal, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure for investigation of Misbehaviour of incapacity of the Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1991;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) “Judge” means the Judge of the Supreme Court appointed for conducting an inquiry under rule 3 ;

(b) “Member” means the Member of the Claims Tribunal established under section 3 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987) and includes the Chairman, Vice-Chairman of such Tribunal against whom investigation of misbehaviour of incapacity is being made under these rules ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Judge to conduct inquiry :—(1) Whenever the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of a Member, it may, after consulting the Chief Justice of India, by notification in the Official Gazette appoint a Judge for the purpose of conducting such inquiry.

(2) Notice of appointment of a Judge under sub-rule(1) shall also be given to such Member.

4. Powers of Judge :—(1) The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908, but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his enquiry.

---

(2) The Judge shall have, for the purposes of discharging his functions under these rules, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;
- (b) requiring the discovery and production of documents ;
- (c) receiving evidence on affidavits ;
- (d) subject to the provisions of sections 123 & 124 of Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office.

[No. 89/TC(RCT)/1-6/Pl.]

ASHOK MALHOTRA, Adviser (Commercial)